Estd. 1926

BCCI BULLETIN

Vol. 56 | February 2025 | No. 02

BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES

प्रभात खबर और बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के संयुक्त तत्वावधान में 'संवाद' का आयोजन

केन्द्रीय बजट 2025-26 में बिहार के लिए खुला पिटारा

इस बार के केन्द्रीय बजट में बिहार को बहुत कुछ दिया गया है। बिहार के लिए कई योजनाए तो आयी हीं, कोसी- मिथिला क्षेत्र को राहत देने का प्रयास भी इस बजट के जरिये किया गया है। बजट के मौके पर प्रभात खबर और बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के संयुक्त तत्वावधान में दिनांक 1 फरवरी 2025 को संवाद का आयोजन किया गया। बजट पेश होने के बाद बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों ने अपनी बातें रखीं। चैम्बर ने बजट को समावेशी विकास पर केंद्रित बताया है। बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की घोषणा का स्वागत किया गया है।

समावेशी विकास पर केंद्रित है यह बजट

"बजट समावेशी विकास पर केंद्रित है। बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी व मखाना के लिए अलग बोर्ड का गठन, पटना व बिहटा एयरपोर्ट के विस्तार, बुद्ध से जुड़े पर्यटन स्थलों का विकास स्वागत योग्य है।"

– **सुभाष कुमार पटवारी,** अध्यक्ष, बी.सी.सी.आई.

उद्यमियों व युवाओं के लिए फायदेमंद

"सभी एमएसएमइ के वर्गीकरण के लिए निवेश और टर्न ओवर की सीमा को क्रमश 2.5 गुणा बढ़ाने व कारोबार सीमा को दोगुना तक बढ़ाने की घोषणा से उद्यमियों के आगे बढ़ने और युवाओं के लिए रोजगार पैदा करने का आत्मविश्वास मिलेगा।"

– **आशीष शंकर,** उपाध्यक्ष, बी.सी.सी.आई.

मरीजों के लिए राहत देने वाला है बजट

"रोगियो विशेषकर कैंसर, दुर्लभ बीमारियों व अन्य गंभीर दीर्धकालिक बीमारियों स पीड़ित रोगियों को राहत प्रदान करने के लिए बजट मैं 36 जीवनरक्षक दवाओं को मूल सीमा शूल्क से पूर्ण छूट वाली दवाओं की सूची में जोड़ने का निर्णय स्वागत योग्य है।"

– **प्रदीप चौरसिया,** उपाध्यक्ष, बी.सी.सी.आई.

किसान व मध्यमवर्ग होंगे लाभान्वित

"बजटीय घोषणाओं से किसानों, एमएसएमइ व छोटे व मध्यमवर्गीय लोग लाभन्वित होंगे। मिथिलाचल क्षेत्र में 50 हजार हेक्टेयर से अधिक भूमि पर बड़ी संख्या में खेती करने वाले किसान लाभान्वित होंगे।"

– **पशुपति नाथ पाण्डेय,** महासचिव, बीसीसीआई

इनकम टैक्स में राहत बड़ा गिफ्ट

"विशेष रूप से हमारे मध्यम वर्ग के लिए इसे सपनों का बजट कहा जा सकता है। बिहार के अनाज से यही कई तरह के उत्पाद तैयार होंगे और इससे रोजगार की भी बड़ी सभावनाएँ सामने आयेंगी। इनकम टैक्स में राहत केन्द्र सरकार का जनता को बड़ा गिफ्ट है।"

– **सुबोध जैन,** कोषाध्यक्ष, बीसीसीआई

एमएसएमई उद्यमियों को मिलेगा लाभ

"बजट में एमएसएमई लिमिट के टर्न ओवर और निवेश की सीमा को बढ़ा दिया गया है। इससे एमएसएमइ उद्यमियों को लाभ मिलेगा। सूबे में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का एलान किया ताकि भविष्य की जरूरतों को पूरा किया जायेगा।"

– **पी. के. अग्रवाल,** पूर्व अध्यक्ष, बीसीसीआई

श्रमिकों व नियोक्ताओं में निराशा

"श्रमिकों के स्वास्थ्य हितों की उपेक्षा की गयी है। अच्छा होता कि प्रत्येक जिले में एक कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय या अस्पताल की स्थापना होने का भी प्रावधान बजट में होना चाहिए था। श्रमिकों व नियोक्ताओं में निराशा है।"

– **सुधि रंजन,** चेयरमैन, उप-समिति (श्रम), बीसीसीआई

पर्यावरण के क्षेत्र में कई अपेक्षाएँ थीं

"बजट 2025 में उद्योग जगत खास कर सूक्ष्म लघु एवं मध्यम इकाइयों की बेहतरी के लिए कई प्रावधानों का जिक्र है। पर्यावरण व

अध्यक्ष की कलम से.....

प्रिय बन्धुओं,

माननीया वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2025–26 में बिहार के लिए पॉच बड़ी घोषणाएं की है। इसमें मुख्य रूप से मखाना बोर्ड का गठन, आइआइटी पटना का विस्तार, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबन्धन संस्थान खोलने, पश्चिमी कोसी कैनाल के लिए अलग से बजट, पटना एवं बिहटा एयरपोर्ट का विस्तार और नये ग्रीन फिल्ड एयरपोर्ट बनाने की घोषणा स्वागत योग्य है। इसके अतिरिक्त बुद्ध से जुड़े पर्यटक स्थलों का विकास, एक सौ से अधिक कानूनों को गैर आपराधिक बनाने, आयकर छूट की सीमा को 12 लाख किये जाने, टैक्स पेयर्स की सुविधा हेतु नया आयकर विधेयक लाने की घोषणा भी स्वागत योग्य है।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए लोन गारंटी सीमा को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ किये जाने, स्टार्टअप को 20 करोड़ तक का कर्ज, नए उद्योगपतियों को दो करोड़ तक का कर्ज आदि की घोषणा औद्योगिक विकास को गति देने में सहायक होगा। **कुल मिलाकर यह बजट राज्य के सर्वांगीण विकास में सहायक होगा।**

इस बजट में बिहार में रेलवे के लिए 90 हजार करोड़ का निवेश प्रस्तावित है। 86,458 करोड़ की लागत से 5346 किमी नई रेल लाइन, दोहरीकरण और आमान परिवर्त्तन की 57 परियोजनाएं प्रगति पर है। 3,164 करोड़ की लागत से 98 अमृत भारत स्टेशनों के लिए पुनर्विकास का कार्य जारी है। 12 बन्दे भारत ट्रेनों का संचालन किया जायेगा। 1783 किमी में कवच सुरक्षा प्रणाली लगाने की प्रक्रिया विभिन्न चरणों में है।

बजट में आयकर स्लैब में किये गये बदलाव के बाद उम्मीद है कि जीएसटी दरों एवं स्लैब में भी बदलाव हो सकता है। माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा है कि जीएसटी दरों वे स्लैब की समीक्षा का का काम लगभग पूरा हो चुका है और कर स्लैब एवं दरों में कटौती पर शीध्र ही जीएसटी परिषद् निर्णय लेगी। अभी जीएसटी एक चार–स्तरीय कर संरचना है, जिसमें 5,12,18 और 28 प्रतिशत के चार स्लैब हैं। विलासिता एवं नुकसानदेह वस्तुओं पर सबसे अधिक 28 प्रतिशत कर लगाया जाता है। दूसरी ओर पैकिंग वाले खाद्य पदार्थों और आवश्यक वस्तुओं पर सबसे कम 5 प्रतिशत कर लागू है। माननीया वित्त मंत्री ने जीएसटी परिषद् में शामिल मंत्रियों से कहा है कि वे जीएसटी दरों पर पूरी गहराई से विचार करें, क्योंकि यह मुद्दा आम लोगों की जरूरतों से जुड़ा है। माननीया वित्त मंत्री ने कहा कि हम दरों के स्लैब कम करने के साथ कम दरें भी चाहते थे।

उम्मीद है, जल्द ही बाढ़ बिजली घर (स्टेज–वन) की अंतिम इकाई से बिजली उत्पादन होने लगेगा। **660 मेगा वाट की इस इकाई से बिहार को 396 मेगा वाट बिजली मिलेगी जो राज्य की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम होगी।**

भागलपुर के पीरपैंती में आठ सौ मेगावाट की तीन ताप विद्युत परियोजनाओं को राज्य कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति प्रदान की है। इन परियोजनाओं का क्रियान्वयन टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी निविदा (TBCB) के माध्यम से होगा। पीरपैती में पहले सौर उर्जा परियोजना स्थापित करने की योजना थी, पर विशेषज्ञ एजेंसियों द्वारा किये गये अध्ययन में पाया गया कि पीरपैती की जमीन सौर उर्जा संयंत्र के लिए उपयुक्त नहीं है। यहॉ ताप विद्युत परियोजना की संभावना को उपयुक्त पाया गया चूॅकि यह कोयला स्रोत के पास स्थित है।

20 फरवरी, 2025 को बिहार विद्युत विनियामक आयोग (BERC) द्वारा नौर्थ/साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0 की ओर से समर्पित टैरिफ पिटिशन 2025–26 पर विद्युत भवन में जन सुनवाई हुई। इस जन सुनवाई में मैंने अपना पक्ष रखा कि बिजली की दर कम हो, Fix Charge घटाया जाये क्योंकि Distribution Company मुनाफे में चल रही है। दो साल पहले Fix Charge चार्ज दुगुना और Unit Rate में 25% की बढ़ोत्तरी हुई थी। मेरे साथ श्री संजय कुमार भरतीया एवं चैम्बर के उर्जा उप समिति के चेयरमैन श्री ए0 के0 पी0 सिन्हा भी उपस्थित थे।

माननीय नगर विकास एवं आवास मंत्री श्री नितिन नवीन की अध्यक्षता में दिनांक 07 फरवरी, 2025 को विकास भवन में होल्डिंग टैक्स नीति को लेकर बैठक हुई जिसमें बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज सहित कई संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। सबों ने 2023 में तत्कालीन विभागीय मंत्री द्वारा लागू होल्डिंग टैक्स को अव्यवहारिक बताया है। विभागीय सचिव एवं अपर सचिव को निर्देश दिया कि टैक्स सिस्टम पर पुनः विचार करें। टैक्स व्यवसासियों पर बोझ न बने।

9 फरवरी, 2025 को चैम्बर ऑफ कॉमर्स त्रिवेणीगंज का स्थापना समारोह–सह–मिलन समारोह आयोजित हुआ था जिसमें उद्घाटनकर्त्ता के रूप में मैं आमंत्रित था। मेरे साथ बतौर मुख्य अतिथि श्री पशुपति नाथ पाण्डेय, महामंत्री एवं विशिष्ट अतिथि श्री अजय कुमार गुप्ता, चेयरमैन, संगठन उप समिति भी आमंत्रित थे। हम तीनों त्रिवेणीगंज गये थे। **मेरे लिए खुशी की बात है कि बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के शताब्दी समारोह वर्ष में चैम्बर ऑफ कॉमर्स त्रिवेणीगंज का उद्घाटन किया जो ऐतिहासिक है।** चैम्बर ऑफ कॉमर्स त्रिवेणीगंज का आयोजन काफी अच्छा था।

बन्धुओ, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी चैम्बर में दिनांक 11 मार्च, 2025 (मंगलवार) को होली मिलन समारोह आयोजित होगा। आप सभी बन्धुओं से आग्रह है कि सपरिवार होली मिलन समारोह में पधारने की कृपा करें।

होली की हार्दिक शुभकामनाऍं।

सादर,

आपका
सुभाष पटवारी

मिट्टी संरक्षण के क्षेत्र में सरकार से कई आपेक्षाए थी।"

– विकास कुमार सिंह
महासचिव, बिहार फ्लाई ऐश ब्रिक इण्डस्ट्रीज एसेसिएशन

बाजार में आयेगी रौनक

"बाजार पर सकारात्मक असर दिखेगा। अभी लोगों की बचत के अभाव से बाजार प्रभावित था। अब लोगों में खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी और बाजार में रौनक आयेगी। इस बजट में बिहार को काफी लाभ मिला है।"

– विनोद कुमार, अध्यक्ष, पाटलिपुत्र सर्राफा संघ

सभी क्षेत्रों पर दिया गया ध्यान

"इस वर्ष का आम बजट बहुत ही संतुलित और सराहनीय है, जिसमें सभी क्षेत्रों पर पूरा–पूरा ध्यान दिया गया है। इस वर्ष के बजट में अपने राज्य के लिए सरकार ने काफी कुछ सोचा है जो प्रशंसनीय है।"

– आलोक पोद्दार, सदस्य, डायरेक्ट टैक्सेशन कमेटी

आम जनता को होगा काफी लाभ

"वित्त मंत्री ने सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए समावेशी विकास का बजट पेश किया है। खासकर बजट में मिडिल क्लास को राहत देते हुए न्यू टैक्स रिजीम में 12 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स माफ

किया गया है।"

– **सुनील सराफ**, चेयरमेन, जीएसटी सबकमेटी, बीसीसीआई

कई बड़ी सौगातें दी गयी

"बजट में बिहार के इंफास्ट्रक्चर को विकसित करने के लिए कई बड़ी सौगातें दी गयी है। बजट में बिहार को विशेष पैकेज दिया गया है। नया एयरपोर्ट और मेडिकल कॉलेज भी बनेगा।"

– **अजय गुप्ता**, कार्यकारिणी सदस्य

मखाना किसानों को मिलेगा बाजार

"मिथिलांचल-कोसी की पहचान मखाना के लिए मखाना बोर्ड का प्रस्ताव रखा इससे मखाना उत्पादन करने वाले लाखों किसानों को फायदा होगा। अब इस बोर्ड के जरिये मखाना किसानों को सीधा बाजार उपलब्ध हो सकेगा।"

– **राकेश कुमार**, वरीय सदस्य, बीसीसीआई

कर में मिलेगा लाभ

"सूबे में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी और उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान बनाने के साथ फुटवियर, चमड़ा उद्योग को बढ़ाने का प्रस्ताव इसका एक प्रमाण है। नयी व्यवस्था में 12 लाख की आय वाले करदाता को कर में 80 हजार का लाभ मिलेगा।"

– **ए. के. पी. सिन्हा**, वरीय सदस्य, बीसीसीआई

बिहार के लिए बजट काफी बेहतर

"मध्यम वर्ग को कर में राहत देते हुए 12 लाख रुपये तक की आय पर कर में छूट दी गयी है। साथ ही टैक्स दर में भी काफी छूट दी गयी है। बिहार के लिहाज से यह बजट काफी अच्छा रहा, कैंसर की दवाएँ सस्ती होगी।"

– **अशीष प्रसाद**, कार्यकारिणी सदस्य, बीसीसीआई

मध्यम वर्ग को समर्पित है केन्द्रीय बजट

"शायद पहली बार मध्यम वर्ग को समर्पित केन्द्रीय बजट पेश हुआ है। आयकर में राहत के साथ कृषि, एमएसएमइ, आधारभूत संरचना, पर्यटन सहित सर्वागीण विकास में बिहार का विशेष ध्यान रखा गया है।" – **महाबीर बिदासरिया**, सदस्य, बीसीसीआई

(साभार : प्रभात खबर, 2.2.2025)

बजट 2025-26 बड़ी घोषणाएँ

• 12 लाख रुपये तक की आमदनी पर अब कोई टैक्स नहीं देना होगा। एक करोड़ आयकरदाताओं को इसका सीधा लाभ मिलेगा • टैक्स प्रणाली में बदलाव के लिए वित्त मंत्री ने अगले सप्ताह संसद में नया टैक्स विधेयक पेश करने की घोषणा की • किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) लोन की सीमा तीन लाख रुपये से बढ़ाकर पाँच लाख रुपये की गई • पाँच विश्वस्तरीय कौशल केन्द्र बनाए जाएंगे जिनकी विदेश के साथ भागीदारी होगी • बुनियादी ढांचे के विकास के लिए राज्यों को 50 वर्ष के लिए 1.5 लाख करोड़ का ब्याज मुक्त कर्ज दिया जाएगा • उड़ान योजना नए स्वरूप में पेश की जाएगी। इस योजना के तहत 120 नए स्थल जोड़े जाएँगे। योजना में चार करोड़ अतिरिक्त यात्रियों को जोड़ने का लक्ष्य • जनविश्वास 2. 0 के तहत 100 कानूनों को मोदी सरकार खत्म करेगी • बिजली की उपलब्धता बढ़ाने के लिए वर्ष 2047 तक कम से कम 100 गीगावाट परमाणु बिजली पैदा करने का लक्ष्य • अब दो प्रापर्टी होने पर आयकरदाता को किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना होगा। पहले यह छूट केवल एक प्रोपर्टी तक ही सीमित थी • टीडीएस पेमेंट में देरी को अपराध की श्रेणी से हटाया जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति या कंपनी समय पर टीडीएस जमा नहीं कर पाती है। लेकिन तय तारीख तक उसका विवरण दाखिल कर देती है तो इसे अब अपराध नहीं माना जाएगा। टैक्स कलेक्शन एट सोर्स (टीसीएस) के नियमों में भी यही बदलाव किया गया • सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई) का निवेश और टर्नओवर लिमिट क्रमशः ढाई गुना और दोगुना किया गया। सरकार के इस कदम से एमएसएमई को ज्यादा कर्ज मिल सकेगा और वे कारोबार विस्तार कर सकेंगे। योजना का उद्देश्य रोजगार बढ़ाना है।

सुशिक्षित समाज : • देश में ग्रामीण इलाकों के सभी सरकारी सेकेंडरी स्कूल ब्राडबैंड से जुड़ेंगे • मेडिकल कालेज में पाँच साल में 75 हजार सीटें बढ़ेंगी। अगले साल 10 हजार सीटें जुड़ेंगी।

जल संरक्षण : • हर घर नल से जल के लिए जल जीवन मिशन योजना की अवधि 2028 तक बढ़ी • अर्बन चैलेंज फंड का बड़ा हिस्सा जलापूर्ति और पानी के पुनः उपयोग पर खर्च होगा।

पर्यावरण संरक्षण : • पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण और वन क्षेत्र का विस्तार होगा • वन की रक्षा करने के लिए नेशनल मिशन फार ए ग्रीन इंडिया को बढ़ावा।

गरीबी उन्मूलन : • शहरी गरीबों के लिए आएगी नई योजना। सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा • पीएम स्वनिधि में 30 हजार रुपये तक की लिमिट का क्रेडिट कार्ड मिलेगा।

स्वस्थ समाज : • अगले तीन वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर केन्द्र स्थापित होंगे • गिग वर्कर्स को जन आरोग्य योजना में स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान की जाएँगी।

जनसंख्या नियोजन : • 10 हजार करोड़ का स्टार्टअप फंड आफ फंड्स बनेगा। रोजगार के अवसर बढ़ेंगे • देश में शीर्ष 50 पर्यटन स्थलों में निवेश के साथ विकास कार्य कराए जाएँगे।

नारी सशक्तीकरण : • पहली बार उद्यमी बनने वाली पाँच लाख एससी-एसटी महिलाओं को दो करोड़ तक का लोन • आंगन-बाड़ी व पोषण 2.0 की शुरूआत होगी, एक करोड़ गर्भवती होंगी लाभान्वित।

सस्ते हुए • कैंसर की 36 दवाएँ • मेडिकल उपकरण • एलईडी • भारत में बने कपड़े • मोबाइल फोन की बैटरी • 82 सामान से सेस हटा • लैदर जैकेट • जूते • पर्स • बेल्ट • इलेक्ट्रिक वाहन • हैंडलूम कपड़े

महंगे हुए • बुने हुए कपड़े • फ्लैट पैनल डिस्प्ले, टीवी डिस्प्ले

" बजट में सरकारी खजाने को भरने के बजाय जनता की जेब भरने पर जोर दिया गया है। यह बजट न केवल देश की वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखता है, बल्कि भविष्य की तैयारी करने में भी मदद करने वाला है।"

– **नरेन्द्र मोदी**, प्रधानमंत्री

(साभार : दैनिक जागरण, 2.2.2025)

बजट 2025 में बिहार.....

12 लाख छूट होने से बिहार के 4.9 लाख आयकर दाता दायरे से बाहर हो जाएँगे

केन्द्रीय बजट 2025-26 में बिहार को लगभग 2 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे। यह पिछले 3 वित्तीय वर्षों में सबसे अधिक है। केन्द्रीय

करों में बिहार की हिस्सेदारी 1.43 लाख करोड़ रुपए होगी जो 2024-25 में मिले 1.25 लाख करोड़ रुपए से 18 हजार करोड़ अधिक है। केन्द्र सरकार ने बिहार को 15 हजार करोड़ रुपए ब्याजमुक्त ऋण की सुविधा दी है। इसे 50 साल में लौटाना है। उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि बिजली क्षेत्र में बतौर ऋण 4 से 5 हजार करोड़ रुपए मिलेंगे। मेडिकल की सीटें बढ़नी हैं, सो बिहार में भी नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। मखाना बोर्ड के गठन से मखाना उत्पादन, प्रसंस्करण और उसकी बिक्री में किसानों को फायदा मिलेगा। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना से युवाओं को कौशल विकास, उद्यमिता और रोजगार के अवसर मिलेंगे। 12 लाख तक की आय टैक्स फ्री होने से बिहार के 4.9 लाख लोग इनकम टैक्स नेट से बाहर हो जाएंगे। राज्य में अभी 5.60 लाख लोग इनकम टैक्स देते हैं।

बीते तीन वित्तीय वर्षों में बिहार की हिस्सेदारी : • **2024-2025 :** 1.73 लाख करोड़ रूपये • **2023-24 :** 1.50 लाख करोड़ रूपये • **2022-23 :** 1.10 लाख करोड़ रूपये

रामायण सर्किट-बोधगया का विकास होगा : बिहार में रामायण सर्किट व बोध गया का विकास किया जाएगा। इसके तहत बिहार में पहले ही राम जानकी मंदिर, वाल्मीकिनगर का विकास किया जा रहा है।

संभावित निवेश : 20 हजार करोड़

किसान क्रेडिट कार्ड की राशि 2 लाख रुपए बढ़ी : किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों को मिलने वाली ऋण राशि 3 लाख की जगह बढ़ाकर 5 लाख रुपए दी गई है।

बिहार में केसीसी : 40 लाख के पास

- **बिहार को 2 अमृत व 8 बंदे भारत मिलेंगी**

पाँच का पंच खेत से लेकर उड़ान तक फोकस

1. मखाना बोर्ड की स्थापना होगी : मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन को बेहतर बनाने के लिए बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी। विश्व का 80 प्रतिशत उत्पादन बिहार में होता है, 5 साल में राज्य में तीन गुणा उत्पादन क्षेत्र और 8 गुणा कीमत बढ़ी है। करीब 40 हजार हेक्टेयर में मखाने की खेती हो रही है।

2. उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान : बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना की जाएगी। यह संस्थान पूरे पूर्वी क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण गतिविधियों को बढ़ावा देगा। इससे किसानों की उपज में मूल्य संवर्धन के माध्यम से उनकी आय में वृद्धि होगी। युवाओं के लिए कौशल, उद्यमिता और रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

3. आईआईटी पटना का क्षमता विस्तार : आईआईटी, पटना में छात्रावास और अन्य बुनियादी ढांचे की क्षमता 75 फीसदी तक विस्तार किया जाएगा। 2014 के बाद शुरू किए गए 5 आईआईटी (पटना भी शामिल) में 6,500 और छात्रों को शिक्षा की सुविधा देने के लिए अतिरिक्त बुनियादी ढांचा निर्मित होगा।

4. राजगीर, भागलपुर व सोनपुर में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे : भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए बिहार में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे बनेंगे। ये पटना हवाई अड्डे की क्षमता के विस्तार और बिहटा में ब्राउनफील्ड हवाई अड्डे के अतिरिक्त होंगे। इसके लिए बिहार सरकार ने राजगीर, भागलपुर और सोनपुर में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों का प्रस्ताव केन्द्र को दिया है।

5. पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के लिए 15 हजार करोड़ : पश्चिमी कोसी नहर एनवायरमेंट रिसोर्स मैनेजमेंट (ईआरएम) के लिए 15000 करोड़ वित्तीय सहायता मिलने की संभावना है। इससे 50,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि सिंचित होगी। कोसी परियोजना के लिए मिथिलांचल क्षेत्र में सिंचाई के लिए पिछले वर्ष केन्द्र से 11000 करोड़ रुपए मिले थे।

“केन्द्रीय बजट प्रगतिशील व भविष्योन्मुखी है। केन्द्र सरकार ने देश के विकास की गति को और बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। बिहार के लिए हुई घोषणाओं से बिहार के विकास को और गति मिलेगी। मखाना बोर्ड की स्थापना से मखाना किसानों को लाभ मिलेगा। बजट में गरीब, युवा तथा किसानों के हित में कई कदम उठाए गए हैं।”

– **नीतीश कुमार**, सीएम

(साभार : दैनिक भास्कर, 2.2.2025)

दीघा से दीदारगंज तक 25 लाख लोग पीएंगे गंगाजल, पानी निकालने को 10 जगहों पर बनेगा इनटेक वेल

शहर में जलापूर्ति के लिए गंगा जल सप्लाई की योजना में बड़ा बदलाव किया गया है। अब दीघा से दीदारगंज तक 10 जगहों पर इनटेक वेल बनाकर शहर भर में पानी की सप्लाई दी जाएगी। इससे 25 लाख आबादी की प्यास बुझेगी। सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि प्रतिदिन भूगर्भ से खींचे जाने वाले 350 एमएलडी जल का दोहन बंद होगा। पुराने प्रोजेक्ट में लागत अधिक होने के चलते जल संसाधन विभाग ने प्लान में बदलाव किया है। अब इस पर होने वाले खर्च का आकलन करने के लिए नया डीपीआर बनाया जाएगा।

फिल्टर कर होगी सप्लाई : नई योजना के तहत दीघा से दीदारगंज के बीच 10 जगहों पर छोटा-छोटा प्लांट लगेगा। इसके लिए इनटेक वेल बनाया जाएगा। इसमें दीघा, एलसीटी घाट, गाँधी मैदान, एनआईटी, पटना सिटी सहित अन्य गंगा घाट शामिल होंगे। इन जगहों पर बनने वाले इनटेक वेल में गंगा का पानी डाला जाएगा। यहाँ पर लगे प्लांटों से पानी को फिल्टर कर टंकी में सप्लाई दी जाएगी। इसके साथ सभी घरों में गंगा जल के पानी की सप्लाई शुरू हो जाएगी।

दिनभर होगी सप्लाई : शहर के लोगों को 24 घंटे पानी की सप्लाई मिलेगी। वर्तमान समय में पटना नगर निगम के द्वारा महज 11 घंटे पानी की सप्लाई दी जाती है। पीएचईडी के रिपोर्ट में भूगर्भ जल का स्तर हर साल नीचे जा रहा है। इस पर रोक लगेगी।

क्या था पुराना प्लान : पुराने प्लान के तहत दीघा में गंगा किनारे बड़ा प्लांट लगा कर घर-घर जलापूर्ति करने की योजना थी। इस पर अधिक खर्च होने की संभावना थी। इस लिए प्लान को बदल कर फिर से डीपीआर तैयार कराया जा रहा है। गंगा जल के साथ सोन नदी के जल को पाइपलाइन के जरिए औरंगाबाद, डेहरी, सासाराम शहरों में पेयजल की आपूर्ति के लिए पहुँचाने की तैयारी चल रही है।

(साभार : दैनिक भास्कर, 2.2.2025)

चैम्बर ऑफ कॉमर्स त्रिवेणीगंज का स्थापना एवं मिलन समारोह आयोजित

एसोसियेट बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज
स्थापना समारोह एवं मिलन समारोह

दीप प्रज्जवलित कर समारोह का उद्घाटन करते श्री सुभाष कुमार पटवारी, अध्यक्ष बीसीसीआई।
उनकी दायीं ओर श्री पशुपतिनाथ पाण्डेय, महामंत्री, बीसीसीआई, श्री अजय कुमार गुप्ता, चेयरमैन, संगठन उप समिति, बीसीसीआई,
श्री भगवान चौधरी, अध्यक्ष, सुपौल व्यापार संघ एवं श्री युगल किशोर अग्रवाल, अध्यक्ष, बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन तथा
बायीं ओर श्री शंभू नाथ, एसडीएम, श्री विपिन कुमार, डीएसपी तथा श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह "पप्पू", अध्यक्ष, सुपौल चैम्बर ऑफ कॉमर्स।

चैम्बर ऑफ कॉमर्स त्रिवेणीगंज
स्थापना समारोह एवं मिलन समारोह

मंचासीन अतिथिगण।

स्थापना समारोह एवं मिलन समारोह

बीसीसीआई अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी को सम्मानित करते
चैम्बर ऑफ कॉमर्स त्रिवेणीगंज के अध्यक्ष श्री सज्जन कुमार अग्रवाल संत।

चैम्बर ऑफ कॉमर्स त्रिवेणीगंज, एसोसियेट बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज (बीसीसीआई) का आयोजन दिनांक 9 फरवरी, 2025 (रविवार) को त्रिवेणीगंज के वंशी चौक स्थित विजय अग्रवाल कॉम्प्लेक्स में हुआ। समारोह की अध्यक्षता चैम्बर ऑफ कॉमर्स त्रिवेणीगंज के अध्यक्ष-सह-वार्ड पार्षद श्री सज्जन कुमार अग्रवाल 'संत' ने की ।

समारोह का विधिवत् उद्घाटन बीसीसीआई के अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी, बीसीसीआई के महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय, संगठन उप समिति, बीसीसीआई के चेयरमैन श्री अजय गुप्ता, व्यापार संघ, सुपौल के अध्यक्ष श्री भगवान चौधरी, बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष श्री युगल किशोर अग्रवाल, सुपौल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह 'पप्पू' एसडीएम श्री शंभु नाथ, एसडीपीओ श्री विपिन कुमार एवं अन्य ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया।

समारोह को सम्बोधित करते हुए बीसीसीआई अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि बीसीसीआई के शताब्दी वर्ष में चैम्बर ऑफ कॉमर्स त्रिवेणीगंज का उद्घाटन किया है जो ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा कि बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज राज्य के समग्र आर्थिक विकास के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर रहा है। व्यापारियों एवं उद्योगपतियों की समस्याओं को समय-समय पर सरकार के समक्ष उठाने के साथ ही सरकार से समन्वय स्थापित कर उनका समाधान चैम्बर द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार को महत्वपूर्ण सलाह एवं सुझाव भी देता है। आज व्यापारियों की जो समस्याएँ हैं, उन्हें अगर चैम्बर के माध्यम से सही तरीके से प्रशासन के समक्ष रखा जायेगा तो उनकी समस्याओं का समाधान हो सकेगा । चैम्बर अध्यक्ष श्री पटवारी ने उन्होने चैम्बर ऑफ कॉमर्स त्रिवेणीगंज के सभी पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी सदस्यों तथा सदस्यों को हार्दिक बधाई दी।

बीसीसीआई के महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय ने कहा कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स त्रिवेणीगंज को जिस किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता होगी बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स हर सम्भव सहायता हेतु प्रतिबद्ध रहेगा। चैम्बर ऑफ कॉमर्स त्रिवेणीगज के स्थापना समारोह में आमंत्रित करने के लिए उन्होंने हार्दिक आभार व्यक्त किया। यह संस्था व्यापारियों की समस्याओं के समाधान में सक्षम हो, यह संस्था उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर हो, यही शुभकामना करता हूँ।

समारोह को सम्बोधित करते हुए बीसीसीआई के संगठन उप

बीसीसीआई के महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय को सम्मानित करते त्रिवेणीगंज चैम्बर के महामंत्री डॉक्टर इन्द्रभूषण प्रसाद।

बीसीसीआई के संगठन उपसमिति के चेयरमैन श्री अजय गुप्ता को सम्मानित करते चैम्बर ऑफ कॉमर्स त्रिवेणीगंज के पदाधिकारी।

चैम्बर ऑफ कॉमर्स त्रिवेणीगंज
स्थापना समारोह एवं मिलन समारोह

समारोह में स्वागत संबोधन करते चैम्बर ऑफ कॉमर्स त्रिवेणीगंज के अध्यक्ष श्री सज्जन कुमार अग्रवाल 'संत'

चैम्बर ऑफ कॉमर्स त्रिवेणीगंज
स्थापना समारोह एवं मिलन समारोह

समारोह को संबोधित करते बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी

चैम्बर ऑफ कॉमर्स त्रिवेणीगंज
स्थापना समारोह एवं मिलन समारोह

समारोह को संबोधित करते बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय

चैम्बर ऑफ कॉमर्स त्रिवेणीगंज
स्थापना समारोह एवं मिलन समारोह

समारोह को संबोधित करते
श्री अजय गुप्ता, चेयरमैन, संगठन उप-समिति, बीसीसीआई।

चैम्बर ऑफ कॉमर्स त्रिवेणीगंज के अध्यक्ष श्री सज्जन कुमार अग्रवाल को माला पहना कर सम्मानित करते बीसीसीआई के अध्यक्ष एवं महामंत्री एवं चेयरमैन संगठन उप समिति।

चैम्बर ऑफ कॉमर्स त्रिवेणीगंज के पदाधिकारियों को एसोसियेट का सर्टिफिकेट प्रदान करते बीसीसीआई के अध्यक्ष, महामंत्री एवं चेयरमैन संगठन उपसमिति।

चैम्बर ऑफ कॉमर्स त्रिवेणीगंज के अध्यक्ष को बीसीसीआई का मेमेन्टो भेंट करते बीसीसीआई अध्यक्ष श्री सुभाष पटवारी।

चैम्बर ऑफ कॉमर्स त्रिवेणीगंज के अध्यक्ष को कॉफी टेबुल भेंट करते बीसीसीआई अध्यक्ष, महामंत्री एवं चेयरमैन, संगठन उप समिति।

श्री अभिनव भारती बीडीओ को चैम्बर का हैण्डबुक भेंट करते बीसीसीआई अध्यक्ष श्री सुभाष पटवारी।

बीसीसीआई की ओर से अतिथियों एवं चैम्बर ऑफ कॉमर्स त्रिवेणीगंज के पदाधिकारियों को बुलेटिन की प्रतियाँ भेंट की गयी।

चैम्बर ऑफ कॉमर्स त्रिवेणीगंज के पदाधिकारियों एवं अतिथियों के साथ ग्रुप फोटोग्राफ

प्रेस ब्रिफिंग देते बीसीसीआई अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी। साथ में महामंत्री एवं चेयर मैन, संगठन उप समिति, बीसीसीआई

समिति के चेयरमैन श्री अजय गुप्ता ने कहा कि व्यावसायियों की जो भी समस्या होती है, उसके समाधान हेतु हम उसी जगह पहुँचते हैं जहाँ उसे न्याय मिल सके। उन्होंने कहा कि बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज सिर्फ व्यावसायिक संगठन ही नहीं है, अपितु सामाजिक संगठन भी है। बीसीसीआई अपने प्रांगण में आर्थिक दृष्टि से कमजोर महिलाओं के लिए निःशुल्क सिलाई-कटाई, ब्युटीशियन, कम्प्युटर प्रशिक्षण भी देता है ताकि प्रशिक्षण ग्रहण कर महिलाएं स्वावलम्बी बन सकें।

सुपौल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्री धमेन्द्र कुमार सिंह 'पप्पु' ने कहा कि हम हर वर्ष पाँच बुजुर्ग व्यावसायियों को सम्मानित करते हैं, साथ ही महिला दिवस पर महिला व्यवसायियों को भी सम्मानित करते हैं।

बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष श्री युगल किशोर अग्रवाल ने कहा कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स व्यापारियों की रीढ़ है। इन्हें किसी से भी प्रतिस्पर्धा नहीं करनी चाहिए ।

व्यापार संघ सुपौल के अध्यक्ष श्री भगवान चौधरी ने कहा सभी संगठनों को साथ लेकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स को व्यापारियों के हितार्थ कार्य करना चाहिए ।

इस अवसर पर एसडीएम श्री शंभू नाथ ने कहा कि त्रिवेणीगंज जैसे छोटे व्यापारिक स्थान में चैम्बर की स्थापना हुई है, यह बड़ी खुशी की बात है। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक स्तर पर जो समस्या व्यवसायियों को होगी उसे सुलझाने का प्रयास रहेगा। चैम्बर ऑफ कामर्स त्रिवेणीगंज प्रशासन एवं व्यवसायियों के बीच सेतु का काम करेगा।

चैम्बर एवं आयकर विभाग के संयुक्त तत्वावधान में सर्राफा व्यवसायियों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

कार्यक्रम को संबोधित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी। उनकी दाँयीं ओर क्रमशः चैम्बर उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर, महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय, कोषाध्यक्ष श्री सुबोध कुमार जैन, श्री पाटलिपुत्र सर्राफा संघ के महासचिव श्री शशि कुमार तथा बांयीं ओर पाटलिपुत्र सर्राफा संघ के अध्यक्ष श्री बिनोद कुमार।

कार्यक्रम में आयकर संबंधी जानकारी देती आयकर अधिकारी श्रीमती सुनन्दा कुमार। उनकी बाँयीं और आयकर निरीक्षक श्री के. डी. साहनी एवं आयकर के अन्य पदाधिकारीगण

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज एवं आयकर विभाग (आसूचना एवं आपराधिक अन्वेषण) पटना के संयुक्त तत्वावधान में दिनांक 13 फरवरी, 2025 को चैम्बर के सभागार में पाटलिपुत्र सर्राफा संघ के सदस्यों के साथ 'निर्दिष्ट वित्तीय लेन-देन विवरण की त्रुटि रहित फाइलिंग' (Errorless filing of Statement of Financial Transctions) एवं 'ई-सत्यापन योजना, 2021 (e-verification scheme, 2021) से संबंधित एक जागरूकता कार्यक्रम (Outreach Programme) का आयोजन किया गया ।

चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि आयकर विभाग जब भी व्यवसायियों को कोई सूचना, संवाद, जानकारी अथवा स्कीम देना चाहता है तो बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज उसमें अहम् भूमिका निभाता रहा है। चाहे वह एमनेस्टी स्कीम हो या वीडीआईएस (VDIS) स्कीम इन सभी को सफल बनाने में चैम्बर ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है एवं भविष्य में भी देता रहेगा।

श्रीमती सुनन्दा कुमार, आयकर अधिकारी (आसूचना एवं आपराधिक अन्वेषण), पटना एवं श्री के0 डी0 साहनी, आयकर निरीक्षक द्वारा विशेष रूप से निर्दिष्ट वित्तीय लेन-देन का विवरण दाखिल करने, SFT-13 (Statement of Financial Transactions) दाखिल करते समय त्रुटियों को दूर करने एवं ई-सत्यापन योजना, 2021 से संबंधित समस्याओं पर समाधान हेतु विस्तृत चर्चा की गई तथा आयकर विभाग के पोर्टल पर त्रुटि रहित डाटा अपलोड करने पर जोर दिया गया । इसके अतिरिक्त इस बात की भी जानकारी दी गयी कि Jewellery क्रेता और बिक्रेता का नाम, पता, पैन व लेन-देन की राशि फार्म संख्या 61A में सही-सही अंकित करें और बिक्री/खरीद करते समय आयकर विभाग के साइट www.incomtax.in पर जाकर 'PAN Validation Facility' से क्रेता-बिक्रेता के पैन की जॉचोंपरान्त ही Sale/Purchase करने की सलाह दी गयी ताकि सूचना सही प्राप्त हो सके। इस सम्बन्ध में पाटलिपुत्र सर्राफा संघ के अंतर्गत आने वाले 'Reporting Entities' से समय पर सुचारू रूप से वित्तीय लेन-देन का विवरण दाखिल करने का सुझाव दिया गया ताकि आयकर विभाग को समय पर सही सूचना प्राप्त हो सके एवं तदनुसार नये कर दाताओं की पहचान कर आवश्यक कार्यवाई की जा सके। पावर प्वाइंट प्रेजेन्टेशन के माध्यम से भी सर्राफा व्यवसायियों को इस संबंध में विस्तृत जानकारी दी गयी।

कार्यक्रम में सर्राफा व्यवसायियों द्वारा पूछे गये प्रश्नों का उत्तर भी आयकर अधिकारियों द्वारा दिया गया ।

कार्यक्रम में आयकर विभाग (आसूचना एवं आपराधिक अन्वेषण), पटना के श्री सूरज कुमार, आयकर अधिकारी (हेड क्वाटर) (I&CI), पटना, श्री कुमार अभय, श्री श्याम जी प्रसाद, श्री आलोक कुमार, श्री अमन कुमार, श्री मणि कुमार, श्री रमनदीप सिन्हा, तथा श्रीमती रंजना कुमारी उपस्थित थे।

चैम्बर की ओर से उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर, महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय, कोषाध्यक्ष श्री सुबोध कुमार जैन, कार्यकारिणी सदस्य श्री अजय गुप्ता, श्री अखिलेश कुमार, श्री रामचन्द्र प्रसाद, सांवल राम ड्रोलिया तथा पाटलिपुत्र सर्राफा संघ के अध्यक्ष श्री बिनोद कुमार, महासचिव श्री शशि कुमार सहित चैम्बर एवं सर्राफा संघ के सदस्य उपस्थित थे।

डीएसपी श्री विपिन कुमार ने कहा कि पुलिस प्रशासन व्यापारियों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह कटिबद्ध है।

इस अवसर पर सभी अतिथियों को चैम्बर ऑफ कॉमर्स त्रिवेणीगंज के पदाधिकारियों द्वारा सम्मानित किया गया।

बीसीसीआई की तरफ से चैम्बर ऑफ कॉमर्स त्रिवेणीगंज के अध्यक्ष श्री सज्जन कुमार अग्रवाल को बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के एसोसियेटशिप का सर्टिफिकेट, मेमेन्टों, कॉफी टेबुल बुक, हैण्ड बुक तथा बुलेटीन की प्रतियाँ भेंट की गई।

बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (BIADA) के परियोजना समाशोधन समिति (PCC) की बैठक

बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (BIADA) के परियोजना समाशोधन समिति (PCC) की बैठक दिनांक 18 फरवरी, 2025 को प्राधिकार के सभाकक्ष में हुई। बैठक की अध्यक्षता श्री कुन्दन कुमार, भा.प्र.से., प्रबन्ध निदेशक, बियाडा ने विडियो कॉफ्रेंसिंग के द्वारा की।

इस बैठक में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी सम्मिलित हुए।

बिहार विद्युत विनियामक आयोग द्वारा नार्थ/साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्युशन कम्पनी लि0 की ओर से समर्पित टैरिफ पिटिशन 2025-26 पर जन सुनवाई

बिहार विद्युत विनियामक आयोग
नॉर्थ / साउथ बिहार पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड

सुनवाई के दौरान अपना सुझाव देते चैम्बर अध्यक्ष।

बिहार विद्युत विनियामक आयोग (BERC) द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2025 को नॉर्थ/साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्युशन कम्पनी लिमिटेड की ओर से समर्पित टैरिफ पिटिशन 2025-26 पर विद्युत भवन में जन सुनवाई हुई। जन सुनवाई BERC के अध्यक्ष श्री आमिर सुबहानी ने की।

BERC के अध्यक्ष के समक्ष बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी ने अपने सुझाव रखें।

जन सुनवाई में श्री ए. के. पी. सिन्हा, चेयरमैन, इनर्जी सब कमिटी, बीसीसीआई एवं श्री संजय भरतिया भी उपस्थित थे।

गैर आवासीय सम्पत्ति कर की बढ़ोतरी के संबंध में चैम्बर का प्रतिनिधिमंडल माननीय नगर विकास एवं आवस मंत्री, अपर सचिव तथा नगर विकास एवं आवास विभाग से मिला

माननीय नगर विकास एवं आवास मंत्री, श्री नीतीन नवीन से वार्ता करते चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी एवं महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय।

श्रीमती वर्षा सिंह, अपर सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सम्मिलित चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी एवं महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय।

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार की ओर से गैर आवासीय सम्पत्ति कर में की गयी बढ़ोतरी पर विचार-विमर्श हेतु श्रीमती वर्षा सिंह, अपर सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार की अध्यक्षता में दिनांक 7 फरवरी, 2025 को एक बैठक हुई। बैठक के पूर्व माननीय नगर विकास एवं आवास मंत्री श्री नीतीन नवीन भी चैम्बर प्रतिनिधिमंडल से मिले।

उक्त बैठक में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी एवं महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय सम्मिलित हुए।

चैम्बर अध्यक्ष ने 'पंख महिला हाट' का अवलोकन किया

भूमिहार महिला समाज द्वारा आयोजित चार दिवसीय पंख महिला हाट दिनांक 7 फरवरी, 2025 को शुरू हुआ जो 10 फरवरी, 2025 तक चला। इस हाट में किसान चाची, ज्वेलरी प्रोडक्ट, किचन से जुड़े उत्पाद, हैंडलूम, अचार, पापड़ जैसे उत्पादों का स्टॉल लगाया गया था। भूमिहार महिला समाज की संस्थापिका श्रीमती प्रिति प्रिया ने बताया कि इस हाट के आयोजन का उद्देश्य उपर्युक्त उत्पादों को बाजार प्रदान करना एवं सही कीमत दिलाना है और हम इन गुणवत्तापूर्ण उत्पादों को बाजार तक पहुँचाने में सफल हो रहे हैं।

इस पंख हाट का बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी ने 10 फरवरी 2025 को अवलोकन किया। इस अवसर पर श्रीमती प्रीति प्रिया संस्थापिका भुमिहार महिला समाज ने चैम्बर अध्यक्ष को अंग वस्त्र एवं पौधा भेंटकर सम्मानित किया। चैम्बर अध्यक्ष ने कहा कि मेले का आयोजन काफी अच्छा है। महिला उद्यमियों के निर्मित उत्पादों को बाजार एवं उचित कीमत दिलाने में पंख हाट उचित माध्यम है।

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक

SBI
राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति, बिहार
90वीं, 91वीं एवं 92वीं (संयुक्त) त्रैमासिक बैठक
संयोजक : भारतीय स्टेट बैंक
17 फरवरी 2025, ताज सिटी सेंटर, पटना

माननीय उप-मुख्यमंत्री-सह वित्त, वाणिज्य-कर मंत्री, बिहार श्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में दिनांक 17 फरवरी, 2025 को राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC), बिहार की 90वीं, 91वीं एवं 92वीं (संयुक्त) त्रैमासिक बैठक होटल ताज सिटी सेंटर में हुई। बैठक में चैम्बर की ओर से अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी शामिल हुए।

प्रदेश के लिए 5 वर्ष में दोगुनी हुई रेलवे की बजट राशि

कुछ अलग **मोकामा, भागलपुर में रेल पुल की सौगात, रेलवे के तिहरीकरण और चार लाइन की परियोजनाएँ भी बिहार को मिलीं**

2 सालों में मिली 12 वंदे भारत ट्रेनें बिहार को, पहली अमृत भारत ट्रेन भी मिली

बिहार में रेलवे अवसंरचना और सुविधाओं के विकास के लिए बजट की राशि दोगुनी हो गई है। वर्ष 2021 में रेलवे के विकास के लिए 5150 करोड़ रुपये मिले थे जो इस बार दस हजार 66 करोड़ हो गए। पिछले साल बिहार में रेलवे के लिए 10033 करोड़ मिले थे।

इन पाँच सालों में बिहार में दो मेगा पुलों की सौगात मिली। इससे महत्वपूर्ण रेलखंड पर ट्रेनों की आवाजाही की सुगमता बढ़ेगी। मोकामा में 1471 करोड़ की लागत से राजेन्द्र सेतु के समानांतर नए रेल पुल के निर्माण का काम अंतिम चरण में है। इसके बनाने से हावडा डीडीयू के साथ-साथ आसपास के स्टेशनों पर रेल यातायात सुगम होगा। संरक्षा मानक भी बेहतर होंगे और राजेन्द्र सेतु के पास ट्रेनें नहीं अटकेंगी। पिछले वर्ष भागलपुर में विक्रमशिला से नवगछिया के कटरिया रेल स्टेशन तक गंगा नदी पर नए पुल के निर्माण को मंजूरी मिली है। इस योजना पर कुल 2549 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

पटना टैक्स कॉन्फ्रेंस 2025 आयोजित

PATNA
PATNA TAX CO... 2025

पटना टैक्स कॉन्फ्रेंस में चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी को पुष्पगुच्छ से सम्मानित करते पटना उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश श्री राजीव रंजन प्रसाद। साथ में चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल।

चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल को पुष्पगुच्छ से सम्मानित करते पटना उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश श्री राजीव रंजन प्रसाद।

पटना टैक्स कॉन्फ्रेंस में उपस्थित श्री सुभाष कुमार पटवारी, चैम्बर अध्यक्ष, श्री पी. के. अग्रवाल, चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष एवं श्री आशीष प्रसाद चैम्बर के कार्यकारिणी सदस्य।

ALL INDIA FEDERATION OF
ACTITIONERS(EZ)
Jointly with
BIHA ME TAX BAR ASSOCIATION
PATNA
NFERENCE 2025
On
February'2025

पटना टैक्स कॉन्फ्रेंस में धन्यवाद ज्ञापित करते चैम्बर के कार्यकारिणी सदस्य श्री आशीष प्रसाद।

ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टीशनर्स एवं बिहार इनकम टैक्स बार एसोसियेशन द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक 8 फरवरी, 2025 को स्थानीय होटल ताज सिटी सेन्टर में ''पटना टैक्स कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन किया गया।

इस कॉन्फ्रेंस में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी, पूर्व अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल, जीएसटी सब कमिटी के चेयरमैन श्री सुनील सराफ एवं कार्यकारिणी सदस्य श्री आशीष प्रसाद सम्मिलित हुए।

कॉन्फ्रेंस में चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी एवं पूर्व अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल को पटना उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश श्री राजीव रंजन प्रसाद के द्वारा सम्मानित किया गया।

धन्यवाद ज्ञापन श्री आशीष प्रसाद ने किया।

इस बीच 12 वंदे भारत ट्रेनें और 98 स्टेशनों को अमृत भारत योजना के तहत विकास का प्रावधान भी किया गया है। इन 12 बंदे भारत ट्रेनों से राज्य के 15 जिले जुड़े हैं और इनका 22 जगहों पर ठहराव दिया गया है। पटना हावड़ा वंदे भारत, पटना राँची वंदे भारत और पटना लखनऊ वंदे भारत की लोकप्रियता देश भर में शीर्ष पर है। योजना के अनुसार अगले डेढ दो सालों में बिहार के विभिन्न शहरों के लिए 12 से 14 नमो भारत ट्रेन चलाने की है। देश की पहली अमृत भारत ट्रेन पिछले साल दरभंगा से नई दिल्ली के बीच शुरू हो चुकी है। पाटलिपुत्र जंक्शन में 200 करोड़ की लागत से वंदे भारत व अन्य ट्रेनों के रखरखाव के लिए कोचिंग काम्प्लेक्स बनाने का काम इसी साल शुरू होगा। अन्य अमृत भारत ट्रेनों को इसी वर्ष चलाने की योजना है। तीन से चार महीने में पटना से नई दिल्ली के लिए इसी साल वंदे भारत स्लीपर भी शुरू होगी।

पाँच साल में बिहार के लिए रेल का बजट : • **वर्ष 2025** : 10066 करोड़ • **वर्ष 2024** : 10033 करोड़ • **वर्ष 2023** : 8505 करोड़ • **वर्ष 2022** : 6549 करोड़ • **वर्ष 2021** : 5150 करोड़

कोसी महासेतु से उत्तर बिहार को संजीवनी मिली : वर्ष 2020 में कोसी रेल महासेतु के निर्माण से उत्तर बिहार को संजीवनी मिली। यह पुल 1934 के भूकंप में क्षतिग्रसत हो गया था। 516 करोड़ की लागत से इस महासेतु के बनने से कोसी और मिथिलांचल के लोगों का सपना साकार हुआ।

(**साभार : हिन्दुस्तान, 4.2.2025**)

(ECR ACHIEVES MILESTONE OF 100% ELECTRIFICATION ACROSS ALL 5 DIVNS

East Central Railway (ECR)has completed electrification across all five of its divisions-Danapur, Sonepur, Samastipur, DDU and Dhanbad - marking a key development in its rail network. This step is part of Indian Railways' broader goal of reducing carbon emissions and modernising its infrastructure.

"The journey of rail electrification in India began on Feb 3, 1925. Over the years, ECR has expanded its electrification projects, improving connectivity and reducing dependency on fossil fuels. The completion of full electrification aligns with Indian Railways'

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज एवं रोटरी क्लब ऑफ पाटलिपुत्रा द्वारा क्वीज का आयोजन

दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करते चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल। साथ में श्री अभय कुमार, डायरेक्टर इकोलॉजी एण्ड इन्भायरनमेंट, श्रीमती स्वाति मोदी, अध्यक्ष, रोटरी क्लब ऑफ पाटलीपुत्रा एवं श्री संदीप सराफ, पूर्व अध्यक्ष, रॉटरी क्लब ऑफ पाटलीपुत्रा।

चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल को सम्मानित करते श्री नवीन गुप्ता, रोटरी क्लब ऑफ पाटलीपुत्रा के पूर्व अध्यक्ष, श्रीमती स्वाति मोदी, अध्यक्ष, रॉटरी क्लब ऑफ पाटलीपुत्रा एवं श्री अभय कुमार, डायरेक्टर इकोलॉजी एण्ड इन्भायरनमेंट।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज एवं रोटरी क्लब ऑफ पाटलिपुत्रा के संयुक्त तत्वावधान में चैम्बर के साहू जैन हॉल में दिनांक 9 फरवरी, 2025 को SAEVUS ECO ACHIEVERS QUIZ PATNA EDITION 2024-2025 आयोजित किया गया। इस प्रतियोगिता में पटना के स्कूल के छात्र-छात्राओं ने भाग लिया।

इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के पूर्व अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल उपस्थित थे।

कार्यक्रम का उद्घाटन विशिष्ट अतिथि श्री पी. के. अग्रवाल ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया।

श्री अग्रवाल ने कहा कि इस क्विज प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य स्कूली छात्रों में पर्यावरण एवं वन्य जीवों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।

क्विज का संचालन प्रसिद्ध क्विज मास्टर राधिका पद्मनाभम ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता रोटरी क्लब के पूर्व अध्यक्ष श्री संदीप सराफ तथा संयोजन श्री अनिल रिटोलिया ने किया।

क्विज प्रतियोगिता में डीपीएस, पटना ने प्रथम तथा डॉन बास्को और संट कैरेंस ने क्रमशः दूसरा एवं तीसरा स्थान प्राप्त किया।

---

commitment to sustainability," ECR's chief public relations officer (CPRO) Saraswati Chandra said.

He added that ECR has also been working towards reducing its carbon footprint by adopting solar energy. "We are Installing solar panels to generate clean energy as part of our strategy to power railway Infrastructure in an environmentally responsible manner," he said.

To further sustainability efforts, green station buildings are being developed to enhance energy efficiency and environmental conservation. These structures incorporate renewable energy sources, rainwater harvesting and eco-friendly materials to minimise the environmental impact of railway operations.

Sonepur divisional railway manager (DRM) Vivek Bhushan Sood said, "With the completion of 100% electrification in the division, we have also undertaken a large-scale sapling plantation drive to improve air quality and create green spaces around railway stations and tracks." He added that this initiative would help counteract the effects of urbanisation and climate change.

Danapur DRM Jayant Kumar Choudhary 'described the electrification milestone as "a major step in modernising rail infrastructure while advancing sustainability goals." He highlighted ongoing efforts such as integrating solar power, developing green station buildings and sapling plantation drives as tangible measures contributing towards environmental responsibility.

Pointing out the operational advantages of electric locomotives, CPRO Chandra said, "They have a greater hauling capacity compared to diesel locomotives, making them more efficient for railway operations." ***(Source : T. O. I., 7.2.2025)***

पाँचवीं इकाई से बिजली उत्पादन जल्द

इसके शुरू होते ही बाढ़ बिजली घर की सभी इकाइयाँ चालू हो जाएँगी

जल्द ही बाढ़ बिजली घर (स्टेज-एक) की अंतिम इकाई से बिजली उत्पादन होने लगेगा। बिजली घर का काम अंतिम चरण में आ गया है। बिजली उत्पादन की प्रक्रिया जोरों पर है।

उम्मीद है कि आगामी एक-दो महीने के भीतर इस बिजली घर से उत्पादन शुरू हो जाए। 660 मेगावाट की इस इकाई से बिहार को 396 मेगावाट बिजली मिलेगी जो राज्य की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम होगी। स्टेज एक के तहत 660 मेगावाट की तीन इकाई का निर्माण हो रहा है। स्टेज-एक की पहली इकाई से वाणिज्यिक उत्पादन का लोकार्पण नवम्बर 2021 में हुआ था। उस यूनिट से बिहार को 396 मेगावाट बिजली मिल रही है। पिछले साल स्टेज एक की दूसरी इकाई चालू हुई और उससे भी बिहार को 396 मेगावाट बिजली मिल रही है। जबकि स्टेज दो में 660 मेगावाट की दो इकाइयों (यूनिट 4 और 5) से क्रमशः 15 नवम्बर, 2014 और 18 फरवरी, 2016 से बिजली उत्पादन हो रहा है। अब स्टेज एक की तीसरी व बाढ़ बिजली घर की अंतिम

इकाई से उत्पादन शुरू करने की प्रक्रिया चल रही है। अधिकारियों के अनुसार बिजली उत्पादन से संबंधित सभी प्रक्रियाओं को पूरा कर लिया गया है। रूस से एक उपकरण मंगवाया गया है जो भारत आ चुका है। गंगा नदी के रास्ते हल्दिया से उस उपकरण को बाढ़ मंगवाया गया है। इसके बाद बिजली उत्पादन का ट्रायल शुरू होगा। एनटीपीसी के अधिकारियों ने कहा कि बाढ़ बिजली घर से व्यावसायिक उत्पादन शुरू करने के पहले इसे लगातार तीन दिनों (72 घंटे) तक चलाया जाएगा। अगर यह अपनी क्षमता के अनुसार फुल लोड पर चलने में कामयाब रहा तो फिर इस इकाई से व्यावसायिक उत्पादन शुरू हो जाएगा।

(साभार : हिन्दुस्तान, 5.2.2025)

होल्डिंग टैक्स होगा कम, सरकार करेगी विचार

राज्य में होल्डिंग टैक्स नीति में बदलाव होगा। वर्ष 2023 में तेजस्वी यादव के बतौर नगर विकास एवं आवास मंत्री रहते लागू की गई होल्डिंग टैक्स नीति पर सरकार फिर से विचार करेगी। इसमें खासकर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को टैक्स के भारी बोझ से राहत मिल सकती है।

पटना के विकास भवन में नगर विकास एवं आवास मंत्री नितिन नवीन की अध्यक्षता में होल्डिंग टैक्स नीति को लेकर बैठक की गई। इसमें बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के दरभंगा, भागलपुर, गया सहित कई शहरों के प्रतिनिधियों ने 2023 में तत्कालीन विभागीय मंत्री तेजस्वी यादव द्वारा लागू किए गए होल्डिंग टैक्स को अव्यावहारिक बताया। इससे व्यवसायिक वर्ग एवं शहरवासियों पर होल्डिंग टैक्स का भारी बोझ होने की बात कही गई। मंत्री और विभागीय सचिव ने उनकी सारी बातों को सुनने के बाद होल्डिंग टैक्स 2023 पर पुन: विचार करने को कहा। उन्होंने कहा कि जो भी अव्यावहारिक बढ़ोतरी हुई है उस पर सरकार फिर से विचार करते हुए इसे पूरे बिहार में समरूपता के साथ लागू करने का प्रयास करेगी। मंत्री ने कहा कि कई जिलों से होल्डिंग टैक्स प्रणाली से संबंधित समस्याएँ सामने आ रही थीं, जिसके बाद विभागीय सचिव और अपर सचिव को निर्देश दिया गया है कि इस पर अलग-अलग व्यावसायियों के साथ बैठकर उनसे चर्चा करें और टैक्स सिस्टम पर पुन: विचार करें।

"होल्डिंग टैक्स का मुख्य उद्देश्य सुविधा देना है। टैक्स की मदद से नगर निकायों का विकास होता है, लेकिन यह टैक्स व्यवसायियों पर बोझ ना बन जाए इसके लिए भी पुन: विचार किया जा रहा है।" **– नितिन नवीन, मंत्री**

व्यावसायिक भवनों का तीन गुना तक बढ़ा था टैक्स : सितम्बर, 2023 में शहरी क्षेत्र के गैरआवासीय (व्यावसायिक) भवनों का होल्डिंग टैक्स डेढ़ से तीन गुना तक बढ़ाया गया था। उस समय तेजस्वी यादव नगर विकास एवं आवास मंत्री थे। सबसे अधिक तीन गुना होल्डिंग टैक्स की बढ़ोतरी होटल, हेल्थ क्लब, जिमनेजियम, क्लब, विवाह-हाल, वाणिज्यिक कार्यालय, बीमा कंपनियों के कार्यालय, बैंक, निजी अस्पताल और नर्सिंग होम के लिए की गई थी। निजी स्कूल-कालेज, कोचिंग, और छात्रावास का टैक्स भी डेढ़ गुना किया गया था। आवासीय भवनों से किराया लेकर व्यावसायिक इस्तेमाल करने वालों पर भी टैक्स की दर बढ़ाई गई थी।

(साभार : दैनिक जागरण, 8.2.2025)

बिहार सरकार

वाणिज्य कर विभाग

जीएसटी अधिनियम के अन्तर्गत अनिबंधित व्यक्ति से व्यवसायिक प्रयोजनों के लिए किराये पर ली गई संपत्ति पर जीएसटी की देयता जीएसटी अधिनियम के अन्तर्गत निबंधित व्यक्ति के द्वारा यदि किसी अनिबंधित व्यक्ति से किराये पर कोई अचल सम्पत्ति ली जाती है तो प्राप्तकर्ता किरायेदार का यह दायित्व है कि वे कर का भुगतान RCM व्यवस्था के अन्तर्गत नगद रूप में करते हुए अपना जीएसटी रिटर्न ससमय दाखिल करना सुनिश्चित करें।

यह व्यवस्था दिनांक 10.10.2024 से लागू है।

इसका उल्लंघन करने पर कर के साथ-साथ ब्याज एवं पेनाल्टी की भी देनदारी होगी। अत: संबंधित करदाताओं को सुझाव दिया जाता है कि इसका अनुपालन करते हुए ससमय कर का भुगतान सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

अधिक जाकारी के लिए विभागीय हेल्पडेस्क या स्थानीय विभागीय कार्यालय में कार्यरत Facilitation Centre से सम्पर्क कर सकते हैं।

Help desk Nos. -
0612-2233512, 2233513, 2233514, 2233515, 2233516
Toll Free No. : 18003456102

राज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव
वाणिज्य कर विभाग, बिहार

(साभार : दैनिक भास्कर, 10.2.2025)

जीएसटी दरें कम करने, स्लैब घटाने पर फैसला जल्द

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि जीएसटी दरों की समीक्षा का काम लगभग पूरा हो चुका है और जल्द ही परिषद स्लैब की संख्या और दरों में कमी पर फैसला लेगी। वर्तमान में जीएसटी एक चार स्तरीय कर संरचना है, जिसमें 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत की स्लैब है। विलासिता से जुड़ी वस्तुओं पर 28 प्रतिशत का उच्चतम कर लगाया जाता है, जबकि पैक किए गए खाद्य पदार्थ और आवश्यक वस्तुएँ सबसे कम पाँच प्रतिशत की स्लैब में हैं। बता दें कि सीतारमण की अध्यक्षता वाली परिषद ने जीएसटी दरों में बदलाव के साथ-साथ स्लैब को कम करने का सुझाव देने के लिए मंत्रियों का एक समूह (जीओएम) गठित किया किया था।

वित्त मंत्री ने एक कार्यक्रम में कहा जीएसटी दरों को तर्कसंगत और सरल बनाने का काम करीब तीन वर्ष पहले शुरू हुआ था। अब काम इसका लगभग पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि परिषद में शामिल राज्यों के वित्त मंत्रियों से दरों पर अधिक गहराई से विचार करने को कहा, क्योंकि वे आम लोगों द्वारा उपभोग की जाने वाली रोजमर्रा की वस्तुओं से संबंधित हैं। मंत्री ने कहा कि देश की आर्थिक बुनियाद मजबूत है और कोई संरचनात्मक मंदी नहीं है। उन्होंने कहा कि बजट में कर राहत प्रधानमंत्री की करदाताओं के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है और उन्होंने उन अटकलों का खंडन किया कि यह कदम दिल्ली विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर उठाया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पुरानी कर व्यवस्था को बंद करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

पूंजीगत व्यय में नहीं आई कमी : सीतारमण

पूंजीगत व्यय से जुड़े एक सवाल पर वित्त मंत्री ने कहा कि इसमें कमी नहीं आई है, बल्कि यह बढ़कर 11.21 लाख करोड़ रुपये हो गया है, जो जीडीपी का 4.3 प्रतिशत है। वित्त मंत्री 2025-26 के लिए बजट के लिए बजट में पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) पर 11.21 लाख करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव रखा गया था, जो वित्त वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमानों में 10.18 लाख करोड़ रुपये से अधिक है। वित्त वर्ष 2023-24 में यह 10 लाख करोड़ रुपये, वित्त वर्ष 2022-23 में 7.5 लाख करोड़ रुपये, वित्त वर्ष 2021-22 में 5.54 लाख करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2020-21 में 4.39 लाख करोड़ रुपये था। बजट में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.4 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है और वित्त वर्ष 2024-25 के लिए लक्ष्य को 10 आधार अंकों से घटाकर जीडीपी का 4.8 प्रतिशत कर दिया गया है।

(साभार : दैनिक जागरण, 5.2.2025)

अत्यावश्यक सूचना

बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन (वस्त्र एवं चर्म) नीति-2022 की कंडिका 12.8 में संशोधन किया गया है जो निम्न है :

(i) चरण-1 : चरण-1 की मंजूरी के लिए अब आवेदन अधिकतम 30 जून, 2026 तक उद्योग विभाग के सिंगल विण्डो क्लियरेंस पोर्टल पर जमा किया जा सकेगा।

(ii) वित्तीय मंजूरी : वित्तीय मंजूरी के लिए अब आवेदन उद्योग विभाग के सिंगल विण्डो पोर्टल पर अधिकतम 30 जून, 2027 तक जमा किया जा सकेगा।

उक्त सम्बन्ध में उद्योग विभाग, बिहार सरकार द्वारा संकल्प ज्ञापांक 502 दिनांक 04 फरवरी, 2025 की प्रति सदस्यों की सूचनार्थ नीचे प्रकाशित की गयी है :-

बिहार सरकार
उद्योग विभाग
संकल्प

बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्याहन (वस्त्र एवं चर्म) नीति, 2022 की कंडिका 12.8 में संशोधन।

राज्य सरकार द्वारा राज्य में कपड़े एवं चमड़े के क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु **"बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन (वस्त्र एवं चर्म) नीति, 2022"** लागू है। इस नीति के लागू होने के पश्चात् राज्य में कपड़े एवं चमड़े के क्षेत्र में निवेशकों को काफी प्रोत्साहन मिला है। उद्योग विभाग द्वारा इन्वेस्टर्स मीट आदि के माध्यम से अधिक-से-अधिक इकाईयों को राज्य में उद्योग लगाने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है। परन्तु अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय बाजार में अधिक उत्पादन एवं कम माँग होने के कारण वस्त्र एवं चमड़ा उद्योग की स्थिति वर्ष 2022-23 में अच्छी नहीं रही। अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर मांग कम होने के कारण वस्त्र एवं चमड़ा निर्माण में लगी कम्पनियों द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 मे क्षमता विस्तार नहीं किया गया। अप्रैल, 2023 से बाजार में माँग में सुधार होना प्रारम्भ हुआ। इन्वेस्टर्स मीट के दौरान वस्त्र एवं चर्म क्षेत्र की कंपनियों एवं संघों ने भी बिहार की "वस्त्र एवं चर्म नीति" की काफी सराहना की है एवं इस नीति के अवधि विस्तार का अनुरोध किया है।

2. बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन (वस्त्र एवं चर्म) नीति, 2022 की कंडिका-12.8 में उद्योग विभाग के संकल्प ज्ञापांक- 1956 दिनांक- 10.07.2023 द्वारा संशोधन करते हुए प्रोत्साहन प्राप्त किये जाने हेतु चरण-1 के मंजूरी के लिए आवेदन देने की अवधि का विस्तार 30 जून, 2024 तक तथा वित्तीय मंजूरी के लिए आवेदन देने की अवधि का विस्तार 30 जून, 2025 तक किया गया था। उक्त अवधि के विस्तार की आवश्यकता है ताकि वस्त्र एवं चमड़े की कम्पनियाँ राज्य में इन क्षेत्रों में निवेश करते हुये इकाई लगा सके।

तदालोक में बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन (वस्त्र एवं चर्म) नीति, 2022 की कंडिका-12.8 में चण-1 के मंजूरी के लिए आवेदन की तिथि तथा वित्तीय मंजूरी की तिथि से संबंधित प्रावधान निम्न प्रकार संशोधित किया जाता है:-

कंडिका - 12.8 - उद्यमियों एवं उद्योग विभाग द्वारा समय-सीमा का पालन

(i) चरण 1 - चरण -1 की मंजूरी के लिए आवेदन अधिकतम 30 जून, 2026 तक उद्योग विभाग के सिंगल विण्डो क्लीयरेंस पोर्टल पर जमा किया जा सकेगा।

(ii) वित्तीय मंजूरी - वित्तीय मंजूरी के लिए आवेदन उद्योग विभाग के सिंगल विण्डो क्लीयरेंस पोर्टल पर अधिकतम 30 जून, 2027 तक जमा किया जा सकेगा।

3. उक्त पर मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 04.02.2025 के मद संख्या -01 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह०/-
(बन्दना प्रेयषी)
सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- 502 / पटना, दिनांक 04.02.2025 सं. सं. -4तक. / टेक्सटाईल पॉलिसी/152/2021

प्रतिलिपि :- मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव /मंत्री, उद्योग विभाग के आप्त सचिव / मुख्य सचिव, बिहार, पटना के विशेष कार्य पदाधिकारी / विकास आयुक्त, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

उद्योगों से जुड़े सैकड़ों प्रविधान होंगे खत्म

सरकार ने 11 से अधिक मंत्रालयों के साथ मिलकर तैयार किया जन विश्वास बिल 2.0, बजट सत्र में हो सकता है पेश

मैन्यूफैक्चरिंग और अन्य प्रकार के कारोबार को आसान बनाने के लिए सरकार जल्द ही जन विश्वास बिल 2.0 को संसद में पेश कर सकती है। उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआइआइटी) के मुताबिक जन विश्वास बिल के तहत 100 से अधिक प्रविधानों को समाप्त किया जाएगा। 11 से अधिक मंत्रालयों के साथ मिलकर जन विश्वास बिल 2.0 तैयार किया जा रहा है। इन सभी मंत्रालयों से जुड़े कई नियमों को समाप्त किया जाएगा। इनमें मोटर वाहन कानून के प्रविधान भी शामिल है। इससे पहले के जनविश्वास बिल के तहत 183 प्रविधानों को समाप्त किया गया।

मैन्यूफैक्चरिंग के प्रोत्साहन के लिए सरकार औद्योगिक यूनिट के निरीक्षण का तरीका भी बदलने जा रही है। गत एक फरवरी को पेश बजट में औद्योगिक सहूलियत को बढ़ाने की घोषणा की गई है।

डीपीआइआइटी के सचिव अमरदीप सिंह भाटिया ने बताया कि राज्यों के साथ मिलकर औद्योगिक निरीक्षण के तरीके में सुधार किया जाएगा। एक निश्चित समय में निरीक्षण करना होगा और आनलाइन पोर्टल पर बताना होगा कि यूनिट में क्या कमी है। इस प्रकार के कई बदलाव आ सकते हैं। उन्होंने बताया कि जन विश्वास बिल के माध्यम से प्रविधानों को कम करने और अन्य नियामक के बोझ को हल्का करने का मुख्य मकसद मैन्यूफैक्चरिंग की लागत को कम करना है। बजट में मैन्यूफैक्चरिंग मिशन लांच करने की घोषणा की गई है। मिशन के लिए 100 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। मिशन भी

कारोबारी सहूलियत बढ़ाने, उद्योग के लिए तकनीक व कुशल श्रमिक उपलब्ध कराने एवं गुणवता वाले उत्पाद तैयार करने के लिए फ्रेमवर्क तैयार करेगा। हालांकि अभी यह तय नहीं है इस मिशन का प्रमुख कौन होगा।

मैन्यूफैक्चरिंग को बढ़ाने का प्रयास मेक इन इंडिया से लेकर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जैसी स्कीम से किया जा रहा है। हालांकि अब भी देश के जीडीपी में मैन्यूफैक्चरिंग की हिस्सेदारी 15 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकी है। **(साभार : दैनिक जागरण, 5.2.2025)**

गाँवों में लोन बांटने को शिविर लगाएंगे बैंक : उपमुख्यमंत्री

बिहार के गाँवों में लोन बांटने को बैंक शिविर लगाएंगे। बैंक कृषि के अतिरिक्त सहकारिता, पशुपालन और सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के विकास के लिए लोन का प्रवाह बढ़ाने में सहयोग करेंगे। चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति में करीब 45 दिन शेष रह गए हैं। बैंकों द्वारा लोन वितरण से राज्य में साख-जमा अनुपात (सीडी रेसियों) में बढ़ोतरी होगी और बिहार के विकास में बैंकों की प्रमुख भागीदारी होगी।

उपमुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति की 90वीं, 91वीं और 92वीं (संयुक्त) त्रैमासिक बैठक में अध्यक्षीय संबोधन के दौरान ये बातें कही। उन्होंने साख-जमा अनुपात में अपेक्षाकृत बढ़ोतरी नहीं होने पर नाराजगी जतायी और कहा कि राज्य सरकार हर सहयोग को तैयार है तब बैंक भी बिहार विकास में सहयोग करें। इस पर बैंक प्रबंधन ने भी शिविर लगाने पर सहमति जतायी। उपमुख्यमंत्री श्री चौधरी ने कहा कि बिहार बदल रहा है, इसमें बैंकों की भी अहम भूमिका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बैंकों के सहयोग से बिहार में बदलाव आया है। हाल ही में 1.81 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। बिहार में पाँच ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, छोटे-छोटे एयरपोर्ट, चार एक्सप्रेस-वे का विकास किया जा रहा है, वहीं 25 मेडिकल कॉलेज अस्पताल की स्थापना की जा रही है। 2008 में जहाँ मात्र 1.92 लाख क्यूसेक पानी से बिहार में तबाही हुई थी, वहीं 2024 के जून-जुलाई में 6.5 लाख क्यूसेक पानी नेपाल से छोड़े जाने के बावजूद 200 गाँवों में पानी नहीं गया। बाढ़ और सुखाड़ की जगह बिहार कृषि के विकास के कारण पहचाना जा रहा है।

बैठक में सहकारिता मंत्री डॉ. प्रेम कुमार ने कहा कि बिहार की राशि राज्य के हित में उपयोग हो, बैंक इसे सुनिश्चित करें। वहीं, पशुपालन मंत्री रेणु कुमारी ने बैंकों पर केसीसी के माध्यम से लोन दिए जाने में गैरजरूरी कागजातों की मांग को लेकर नाराजगी जतायी। कहा कि बैंक लोन के आवेदन की मंजूरी या अस्वीकृति की सूचना भी समय पर नहीं देते हैं।

एसएलबीसी की उप समिति का गठन होगा : बिहार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने कहा कि एलएलबीसी की एक उप समिति राज्य स्तर पर गठित की जाएगी। इसी प्रकार, जिला स्तर पर भी समिति का गठन कर वार्षिक लोन वितरण के लक्ष्यों की नियमित समीक्षा की जाएगी। इस समिति में विभिन्न विभागों एवं बैंक के प्रमुख अधिकारी रहेंगे। वहीं, जिलाधिकारी के स्तर पर गठित समिति में हरेक दो माह में बैंकों के कामकाज की समीक्षा की जाएगी। उन्होंने कम सीडी रेसियो वाले जिलों को लेकर एसएलबीसी से अध्ययन कराकर रिपोर्ट देने को कहा ताकि परेशानियों को हल किया जा सके।

राज्य का साख जमा अनुपाल

वर्ष	जमा	साख	अनुपात
2019-20	371783	159987	43.03 प्रतिशत
2020-21	396471	183973	46.40 प्रतिशत
2021-22	431417	228480	52.96 प्रतिशत
2022-23	466583	250375	55.64 प्रतिशत
2023-24	501747	290347	58.71 प्रतिशत
2024-25	541414	317220	58.59 प्रतिशत

(दिसम्बर 2024 (राशि करोड़ में)

बिहार में साख-जमा अनुपात वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक 60 फीसदी होने की उम्मीद : बिहार में चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक साख-जमा अनुपात (सीडी रेसियो) बढ़कर 60 फीसदी होने की उम्मीद है। राज्य में दिसम्बर, 2024 तक बैंकों ने जमा की तुलना में महज 58.59 प्रतिशत ही लोन बांटे हैं, जो कि साख-जमा (सीडी) अनुपात के राष्ट्रीय औसत करीब 78 प्रतिशत की तुलना में कम है। चालू वित्तीय वर्ष के वार्षिक ऋण लक्ष्य 323093 करोड़ की तुलना में 168930 करोड़ ही लोन बांटे गए हैं। चालू वित्तीय वर्ष 2024-2025 के तीन तिमाही के राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) की बैठक एक साथ हुई। इसमें राज्य सरकार ने इसमें बढ़ोतरी करने का निर्देश दिया है। वहीं, एसएलबीसी के अधिकारियों ने चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक सीडी रेशियो में बढ़ोतरी की उम्मीद जतायी।

(साभार : हिन्दुस्तान, 18.2.2025)

रेपो दर में 0.25 अंक की कटौती से बच सकते हैं 4.4 लाख रुपये

रिजर्व बैंक की कटौती के बाद आवास, वाहन और व्यक्तिगत ऋण सस्ते होने की उम्मीद

आरबीआई ने पिछली 11 बार की मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक में रेपो रेट नहीं घटाया और लंबे इंतजार के बाद ब्याज दरें घटा दीं। इस कटौती के बाद आम आदमी के लिए भी सस्ते कर्ज का रास्ता खुल गया है।

कितना होगा फायदा : अगर आपने 50 लाख रुपये का घर कर्ज एक साल पहले 9% ब्याज दर पर 20 साल यानी 240 महीनों के लिए लिया था, तो ऐसे में मूलधन के अलावा कुल ब्याज 58 लाख रुपये तक चुकाना होगा। अब रेपो रेट 0.25% घट गई है। ऐसे में आपका बैंक भी ब्याज दर घटाता है तो आपकी नई ब्याज दर 8.75% हो जाएगी। आप अपनी मासिक किस्त वही रखते हैं तो कर्ज 230 महीनों (19 साल 2 महीने) में खत्म हो जाएगा यानी आपको 10 किस्त कम चुकानी होंगी और इससे आपको 4.4 लाख रुपये के ब्याज की बचत होगी।

क्या करें कर्ज लेने वाले : ग्राहकों के पास दो विकल्प हैं, पहला, किस्त की राशि घटाएँ इससे मासिक बोझ कम होगा या दूसरा, किस्त की संख्या कम करें, इससे कर्ज जल्दी खत्म होगा और कुल ब्याज की बचत होगी। विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि फायदा मासिक किस्त राशि घटाने से ज्यादा किस्तों की अवधि घटाने में है। इससे कर्ज जल्दी

PT.GPO/R-10/NP-15/2017-19 R. N. 4211/62

खत्म होगा और बड़ी बचत होगी। ब्याज दर कटौती का पूरा लाभ उठाने के लिए किस्त की राशि को पहले जैसा रखें। फ्लोटिंग रेट लोन वालों को सीधा फायदा होगा लेकिन फिक्स्ड ब्याज दर वालों को इस कटौती से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि उनकी ब्याज दर पूरी अवधि के लिए पहले से तय होती है। हालांकि ग्राहक चाहे तो बैंक को शुल्क का भुगतान कर फ्लोटिंग ब्याज दर का विकल्प ले सकता है।

इससे घर, वाहन और व्यक्तिगत सहित तमाम तरह के खुदरा लोन की ब्याज दरें भी घटने की उम्मीद है। बैंकों के ज्यादातर लोन अभी रेपो रेट जैसे बाहरी बेंचमार्क से जुड़े हुए हैं, लिहाजा इसमें हुई कटौती का सीधा असर इन कर्ज की ब्याज दरों पर भी पड़ेगा और हर महीने जाने वाली किस्त भी कम हो जाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि आरबीआई आगे भी ब्याज दरों में कटौती कर सकता है।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 8.2.2025)

नया इनकम टैक्स बिल कैसे बना और इसमें क्या है?

20,976 सुझाव मिले, तैयार करने में 60 हजार घंटे लगे

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिनांक 13 फरवरी 2025 को संसद में नया आयकर बिल पेश किया है। यह लोकसभा में पास हो गया। आइए जानते हैं कि इस बिल में क्या खास है?

- **मौजूदा इनकम टैक्स एक्ट कब पारित हुआ था?**

1961 में पारित यह अधिनियम 1 अप्रैल, 1962 से प्रभावी था। इसमें वित्त अधिनियम के तहत 65 बार में 4,000 से ज्यादा संशोधन हुए।

- **नए बिल का मसौदा बनाने में कितनी मशक्कत हुई?**

इनकम टैक्स बिल को आसान समझने लायक बनाने और गैर-जरूरी प्रावधान हटाने के लिए 20,976 ऑनलाइन सुझाव मिले। इनका विश्लेषण किया गया। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी मशविरा किया गया। अतीत में ऐसे संशोधन कर चुके ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के आयकर विभागों से भी सलाह ली गई। 2009 और 2019 में इस संदर्भ में तैयार किए गए दस्तावेजों का अध्ययन भी किया गया।

- **कितनी बड़ी टीम ने इसे अंजाम दिया?**

विभाग के करीब 150 अफसरों की कमेटी ने इस पूरी मशक्कत को अंजाम दिया। नए बिल को अंतिम रूप देने में 60 हजार से ज्यादा घंटे लगे।

- **सेलरीड क्लास के लिए नए बिल में क्या आसान होगा?**

वेतन संबंधी सभी प्रावधान आसानी से समझने के लिए एक ही जगह पर लाए गए हैं, ताकि इनकम टैक्स रिटर्न फाइन करते समय अलग-अलग अध्याय का संदर्भ न लेना पड़े। सेक्शन- 10 के तहत पहले दी जानी वाली कटौती, मसलन ग्रेच्युटी, लीव इनकैशमेंट, पेंशन कम्प्यूटेशन आदि को अब सैलरी चैप्टर में ही लाया गया है।

- **बिल संसद में पेश हो गया, अब आगे क्या?**

बिल संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद कानून का स्वरूप लेगा। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद नए नियमों की अधिसूचना जारी होगी। साथ-साथ सॉफ्टवेयर तैयार करने का भी काम शुरू होगा।

- **क्या पुराने और नए सेक्शंस की कोई मैपिंग उपलब्ध होगी?**

हाँ, आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर सेक्शन-वाइज मैपिंग उपलब्ध कराई जाएगी।

- **बिल में 'पिछले वर्ष' और 'मूल्यांकन वर्ष' की जगह क्या?**

'पिछले वर्ष' और 'मूल्यांकन वर्ष' की जगह 'टैक्स वर्ष' की अवधारणा पेश की गई है। विधेयक में समय-सीमा और गणन अब उस वित्त वर्ष के संदर्भ में है, जिसके लिए आय पर टैक्स लगाया जाना है।

- **टीडीएस और टीसीएस के प्रावधान कैसे सरल बनाए गए?**

टेबल के जरिये टीडीएस और टीसीएस के प्रावधान समझना आसान बना दिया गया है। देश में रहने वाले भारतीयों, एनआरइआई और जहाँ स्रोत पर कटौती (टीडीएस) की जरूरत नहीं है, वैसे मामलों में भुगतान के लिए अलग-अलग टेबल हैं।

- **पुराने व नए प्रावधान कैसे एक साल अस्तित्व में रहेंगे?**

बिल में रिपील और सेविंग्स क्लाउज में संबंधित वर्षों के लिए अनुपालन के विभिन्न पहलुओं का उल्लेख किया गया है। ये पुराने कानून के तहत अर्जित सभी अधिकारों और दायित्वों की रक्षा करेंगे।

(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 14.2.2025)

Statement about ownership and other particulars about newspaper of the Bihar Chamber of Commerce & Industries monthly Bulletin to be published in the first issue every year after last day of February.

Form - IV
(See Rule -8)

1.	Place of Publication	Bihar Chamber of Commerce & Industries, Khem Chand Chaudhary Marg, Patna-800 001
2.	Periodicity of its publication	Monthly
3.	Printer's Name Whether Citizen of India? (If foreigner, state the Country of origin) Address	A. K. Dubey Indian Deputy Secretary Bihar Chamber of Commerce & Industries, Khem Chand Chaudhary Marg, Patna-800001
4.	Publisher's Name Whether Citizen of India? (if foreigner, State the Country of Origin) Addrss	A. K. Dubey Indian Deputy Secretary Bihar Chamber of Commerce & Industries, Khem Chand Chaudhary Marg, Patna-800001
5.	Editor's Name Whether Citizen of India? (If Foreigner, State the Country of Origin) Address	Shri Pashupati Nath Pandey Indian M/s Jugeshwar Pandey New Lalji Tola Patna - 800001
6.	Name and Address of Individual who own the newspaper and partners of Share-holders	Bihar Chamber of Commerce & Industries Khem Chand Chaudhary Marg Patna-800 001

I, A. K. Dubey, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

A. K. Dubey
Publisher

EDITORIAL BOARD

Editor
PASHUPATI NATH PANDEY
Secretary General

Chairman
ASHISH SHANKAR
Bulletin Sub-Committee

Printer & Publisher
A. K. DUBEY
Dy. Secretary

Khemchand Chaudhary Marg, Patna - 800 001 • Ph. : 0612-2677605, 2677505, 2677635
E-mail : bccpatna@gmail.com • Website : www.biharchamber.org

Designed & Printed by : Sharada Enterprises, Ph. : 0612-2667296